Designing of New Facility at National Aeronautical Laboratory, Bangalore to read black box data

874. SHRI HARVENDRA SINGH HANSPAL: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the scientists at the National Aeronautical Laboratory, Bangalore have designed a new device to read the black box data in aircraft, a vital source of information in the event of a crash;

(b) if so, what are the salient features of the said device;

(c) whether Government have decided to examine the black box of the ill-fated A-320 airbus which crashed near Bangalore on the 14th February, 1990 through Scientists of the National Aeronautical Laboratory; and

(d) if not, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN DEPARTMENT OF EDUCATION IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (PROF. M. G. K. MENON): (a) Yes, Sir.

(b) The black-box (DFDR) read out facility that NAL has developed conforms to ARINC-573 standards and caters for Boeing 747 and Airbus 300 operated by Air India. The data is recorded in Harvard bi-phase code at a bit rate of 768 bits per second constituting a subframe. Each subframe has different aircraft parameters represented digitally by a 12 bit word. The interfere unit enables data in the DFDR to be regenerated through a PDP-11/44 computer at Air India.

(c) and (d) Both the DGCA and NAL have the Cockpit Voice Recorder (CVR) decoding facility. DGCA decoded the CVR of the ill-fated A-320 airbus which crashed near Bangalore on the 14th February, 1990. Digital Flight Data Recorder (DFDR) decoding facility developed by NAL for Air India is not compatible to decode the DFDR used in the A-320 aircraft. Hence the Government of India decided to have the DFDR decoding done abroad.

Visit of French Armament Company SOFMA's representative to Delhi

875. SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether a representative of the French Armament Company SOFMA came to Delhi recently; and

(b) if so, what was the purpose of the visit and the subject of his meetings with the officials of Government of India?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (DR. RAJA RAMANNA): (a) and (b) A representative of M/s. SOFMA of France visited New Delhi in January, 1990 for discussions connected with some Naval Projects.

कुल राष्ट्रीय आय का शिक्षा पर खर्च का प्रतिशत

876. सरदार अजीत सिंह अरोड़ा:
श्री राम जेठमलानी:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोठारी आयोग ने 1966 में यह सिफारिश की थी कि कुल राष्ट्रीय आय का छः प्रतिशत शिक्षा पर खर्च किया जाना चाहिए ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि विगत के वर्षों में अपनाई गई शिक्षा नीति में इस सिफारिश को भी स्वीकार किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में शिक्षा पर कुल राष्ट्रीय आय का कितना प्रतिशत खर्च किया गया है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री, साथ में मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (प्रो० एम० जी० के० मेनन): (क) और (ख) कोठारी आयोग (शिक्षा आयोग, 1964-66) ने शैक्षिक खर्चे को वर्ष 1985-86 तक कुल राष्ट्रीय उत्पाद का 6 प्रतिशत तक परियोजनाबद्ध किया । राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1968 में यह उल्लेख किया गया है कि शिक्षा में पूंजीनिवेश में धीरे-धीरे वृद्धि करने का उद्देश्य है ताकि यह खर्चे यथासम्भव यथाशीघ्र राष्ट्रीय आय के 6 प्रतिशत तक पहुंच जाएं और राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में भी इस बात का उल्लेख है कि जबकि वास्तविक अपेक्षाएं अनुश्रवण और समीक्षा के आधार पर समय-समय पर संगनीकृत की जाएंगी और शिक्षा पर परिव्यय सातवीं योजना में नीति के कार्यान्वयन के लिए अनिवार्य सीमा तक बढ़ जायेगा इसके साथ ही इस बात को सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि आठवीं पंचवर्षीय योजना से आगे, यह समान रूप से राष्ट्रीय आय के 6 प्रतिशत तक बढ़ जाएगा।

(ग) केन्द्र तथा राज्य सरकारों के शिक्षा विभागों के वर्ष 1987-88 और 1988-89 के लिए बजट प्रावधान राष्ट्रीय आय का क्रमशः 3.80 प्रतिशत और 3.39 प्रतिशत (शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद) है ।

अनिवार्य शिक्षा के कार्यक्रमों के लक्ष्यों पर निगरानी

877. **सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :**
श्री राम जेठमलानी :

क्या प्रधान मंत्री 26 दिसम्बर, 1989 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 174 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 14 वर्ष की आयु तक के प्रत्येक बालक को अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु प्रगति के कुछ वार्षिक लक्ष्यों को निर्धारित किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री, साथ में मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) और (ख) वर्ष के दौरान किए गए आबंटनों और विगत के निष्पादन के आधार पर प्रत्येक राज्य/संघ शासित प्रदेश के लिए सरकार अतिरिक्त दाखिले के वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करती है । सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत अतिरिक्त दाखिले तथा उपलब्धि के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :

(लाखों में)

वर्ष 1985-90 के लिए अतिरिक्त दाखिला और उपलब्धियों के लक्ष्य

कक्षा I से III

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि
1985-86	51.31	53.07
1986-87	56.61	53.50
1987-88	53.29	38.78
1988-89	56.90	53.35 (सम्भावी)
1989-90	60.22	अभी उपलब्ध नहीं है।